अमृत वाणी

जय उसी की होती है जो अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करते हैं। जय कायरों की कभी नहीं होती।

-जवाहरलाल नेहरू,

कमजोर तबके के साथ मजाक शोभनीय नहीं

शासन गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं बनाती है ताकि यह वर्ग उसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति बेहतर बना सके लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि वास्तविक जरूरत मंद इन योजनाओं का लाभ उठाने में सफल नहीं हो पाते। शिक्षा के क्षेत्र में मिल रहे बढ़ावा के चलते एवं समय के साथ-साथ लोगों में आ रही जागरूकता के चलते आज के युवा शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद उनके लिए रोजगार पाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। माता-पिता भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के पश्चात यह आशा करते है कि अब उन्हें अपने बच्चों से आर्थिक सहारा मिलेगा। शासन भी शासकीय क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार की अनुपलब्धता के मद्देनजर शिक्षित बेरोजगारों के लिए विभिन्न वैकल्पिक रोजगार के माध्यम सृजित करने का प्रयास करती है मगर कई बार ऐसा माध्यम जरूरतमंद युवाओं की पहुंच से इतनी दूर हो जाते है कि उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता।

नगर में ऐसे ही युवाओं के लिए निगम द्वारा कुछ नये दुकानों का निर्माण कराया गया है। इन दुकानों की निविदा भी बुलाई गई है लेकिन निविदा का न्यूनतम मूल्य पांच लाख रूपये रखा गया है जो किसी भी गरीब परिवार के बेरोजगार युवा के पहुंच से बाहर है। यह उनके साथ मजाक नहीं तो क्या है। इसी तरह अगर गौर किया जाये तो चाहे गरीब तबके को दी जाने वाली निःशुल्क लाभ हो अथवा जटिलता अथवा रूकावट उन्हें योजनाओं के लाभ तक पहुंचने नहीं देती।

कमजोर तबके को मिलने वाली पेंशन हो अथवा कोई भत्ता या फिर कोई निःशुल्क वस्तु यह सब कुछ सुनने में जितना प्रिय और सुविधापूर्ण लगता है जमीनी स्तर पर उतना ही जटिल बन जाता है। अनावश्यक औपचारिकताएं, वेहुदा पेचिदगियां एवं भ्रष्टाचार की वाधा एक आम बात है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना का हाल ही देखें। बस्तर जिले में जहां लोगों को ऐसे आवास की सर्वाधिक जरूरत है, वहीं जिले में इसका आलम यह है कि योजना के तहत चयनित लोगों के खाते में किश्तों में दी जाने वाली राशि पिछले तीन महीनों से नहीं डाली जा रही है। अचानक राशि मिलना बंद हो जाने से जहां अनेक लोगों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है वहीं कई लोग कर्ज लेकर काम चला रहे है।

इसी तरह चाहे निःशुल्क शासकीय संस्थान हो अथवा निःशुल्क शासकीय सेवा हर क्षेत्र में ऐसी कमियां और विसंगतियां आसानी से देखी जा सकती है। शासन शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकाधिक प्रेरित करना चाहती है लेकिन संबंधित क्षेत्रों से उन्हें ऐसा सहयोग बहुत कम ही मिल पाता है जिससे वे उस दिशा में प्रोत्साहित हों। यही वजह है कि एक ओर जहां शासन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर शिक्षित युवाओं में निराशा व असंतोष बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि केवल योजनाओं का निर्माण ही नहीं बल्कि उन्हें व्यवहारिक और आम लोगों के पहुंच के लायक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

राज-काज

चिंता तो है पर किस बात की

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब से अपनी सरकार और पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है तभी से कुछ लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गडकरी को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब यदि यह सही भी है तो फिर अपनों को चिंता करनी चाहिए विरोधी क्योंकर चिंता कर रहे हैंए यह विचारणीय है। चिंता तो इस बात को लेकर भी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने आखिर गडकरी की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ेए कहीं यह विपक्ष का कोई नया एजेंडा तो नहींए जिसने गडकरी को हीरो बनाने का काम किया हुआ है। कहने वाले कह रहे हैं कि इसी को राजनीति कहते हैं कि चिंता तो है पर किस बात को लेकर किसी को कुछ पता नहीं। सब हवा.हवाई बातें और चिंता तैर रही है दिमागों में।

फिर मोदी, न बाबा ना!

लोकसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए मतदाता का मन टटोलने से लेकर मन बनाने तक का काम नारों के जरिये किया जा रहा है। यहां कांग्रेस ने श्चौकीदार चोर है का नारा देकर सभी को बतलाने का कार्य किया कि किस तरह से नोटबंदी और राफेल के जरिए मोदी सरकार ने घपले कि तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे के पहले ही पोस्टर लग गए कि मोदी नेवर अगेन, नो मोर मोदी और मोदी , मिस्टेक। इन पोस्टरों पर पार्टी या नेता का नाम नहीं लिखा गया, जिससे साफ नहीं हुआ कि किसने पोस्टर लगाए। यहां टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी यह देखने आ रहे हैं कि आखिर लोग जिंदा कैसे रह गए। बहरहाल पोस्टरों का असर ही है कि लोग एक दूसरे से कहते देखे गए कि फिर से मोदी न बाबा ना।

सरोजिनी नायडू देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं

आज सरोजिनी नायडू जन्म दिवस पर विशेष

अंदेश की आजादी में लाखों लोगों ने भाग लिया और लाखों ने कुरबानी दी। कुछ बिरले हस्तियां होती हैं जो अपने नाम को अजर मर कर जाती हैं, उनमे एक श्रीमती नायडू थी। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 . 2 मार्च 1949 का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवयित्री थीं और बांग्ला में लिखती थीं। बचपन से ही कुशाग्र.बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12हवीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ दी लेक नामक कविता रची। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निज़ाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था सरोजिनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला।

वे 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गईं और पढ़ाई के साथ.साथ कविताएँ भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रैशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया।

1898 में सरोजिनी नायडू, डॉ गोविंदराजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनीं। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गाँधीजी से मिलीं और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गयीं। एक कुशल सेनापति की भाँति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र सत्याग्रह हो या संगठन की बात में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गयीं। संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भाँति गाँव.गाँव घूमकर ये देश.प्रेम का अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजीए हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थीं। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 2, अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनीं और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। भारत की स्वतंत्रता.प्राप्ति के बाद वे उत्तरप्रदेश की पहली राज्यपाल बनीं। श्रीमती एनी बेसेन्ट की प्रिय मित्र और गाँधीजी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1949 को उनका देहांत हुआ। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद, देश को उस लक्ष्य तक पहुँचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था। किन्तु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजिनी नायडू भी एक थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहाए श्मैं अपने को श्क़ैद कर दिये गये जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकीं जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गईं और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। ऐसी हस्तियां इस धरा पर बार बार नहीं आती जो एक बार आती हैं सदा याद रखी जाती हैं। हमें इस हस्तियों से ककुछ सबक सीखना होगा।

आर जैन

(ये लेखक के अपने विचार है)

चोरी और सीनाजोरी

तीन फरवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, उसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। देशवासियों को यह कल्पना ही नहीं रही होगी, कि कोई राज्य सरकार इस तरह पेश आ सकती है मानो वह भारत का हिस्सा न होकर कोई स्वतंत्र इकाई हो। जिस तरह से कलकत्ता में पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने आई सीबीआई की टीम के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने व्यवहार किया। यानी कि सीबीआई की टीम को पूछताछ करने से रोका ही नहीं, उनसे धक्का.मुक्की भी की और एक तरह से उन्हें हिरासत में लिया. वह लोगों को स्तब्ध कर देने वाला था। बिडम्बना यह कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटेष् की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीबीआई और प्रधानमंत्री को दोषी ठहराते हुए उन्हें संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी कहते हुए धरने पर बैठ गई। यह बात तो अपनी जगह पर है, मोदी विरोधी कई नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बढ़.चढ़कर समर्थन दिखाने में कोई कोर.कसर नहीं छोड़ी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी थे।

तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और चन्द्रबाबू नायडू जैसे कुछ नेता तो ममता के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए कलकत्ता भी पहुंच गए। इस संबंध में ममता बनर्जी का कहना था कि कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के निवास पर सीबीआई की जो टीम जा रही थी, उसके पास न्यायालय का वारंट नहीं था। जबकि सच्चाई यह है कि यह जांच सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही की जा रही थी और सीबीआई राजीव कुमार के पास पूछताछ के लिए गई थी, जिसमें कम.से.कम किसी वारंट की आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ शारदा स्कैम और रोजवैली स्कैम को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था, अपितु पश्चिम बंगाल पुलिस को इसमें समुचित सहयोग के लिए भी निर्देशित किया था। लेकिन सहयोग करना तो दूर ममता की पुलिस इसमें तरह.तरह से बाधा खड़ी करने लगी। एक तरह से देखा जाए तो यह सारा मामला बिहार के चारा घोटाले जैसा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के तात्कालिन मुख्यमंत्री लालू यादव ने चारा घोटाले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की थी। जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने घोटाले को ढ़कने का प्रयास मानते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाद के घटना.क्रम से तो सभी परिचित होंगे। लोगों का कहना है कि शारदा.नारदा और रोजवैली के घोटालों को लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसण्आईण्टी गठित की थी, पर सही दिशा में जांच न चलने और लीपापोती के प्रयास को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त घोटालों की जांच जिसमें लाखों लोग प्रभावित थे.सीबीआई को सौंप दिया। यह तक कहा जाता है कि राजीव कुमार ने सही दिशा में जांच करने के बजाय साक्ष्य मिटाने का काम किया। उन्होंने अपने मोबाइल से कई नम्बर और उनका विवरण डिलीट कर दिया।

यह बात अलग है कि डिलीट करने के पूर्व सीबीआई ने उपरोक्त सब कुछ अपनी जानकारी में ले लिया। आरोप यह भी है कि राजीव कुमार ने एक पेन ड्राइव और लाल डायरी जिसमें अभियुक्तों के नाम और विवरण थे उसे भी जांच के लिए सीबीआई को नहीं सौंपा। जबकि सीबीआई को जांच मिलने के पश्चात् नियमानुसार सभी दस्तावेज और जानकारी उसे सौंप दिया जाना चाहिए था। सीबीआई इसी संबंध में राजीव कुमार से पूछतांछ करने के लिए तीन बार नोटिस भेज चुकी थी, पर वह बार.बार बहाने बनाकर सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। तब मजबूर होकर सीबीआई को पूछताछ करने उनके घर जाना पड़ा, जिसका अंजाम सभी देख ही चुके हैं। यह बात अलग है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी की तर्ज पर राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ से बच नहीं पाए, क्योंकि सीबीआई की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें सीबीआई से पूछताछ करने के लिए उपलब्ध होने को कहा और शिलांग में उनसे पूछताछ हो ही रही है। अब ममता इसे भी अपनी नैतिक जीत बता रही हैं। वस्तुतः यह ममता की नैतिक जीत नहीं, राजीव कुमार प्रकरण के बहाने वह पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं। इस घटना के चलते जनमानस में यह गंभीर आशंका व्याप्त हो गई है कि उपरोक्त घोटालों में कहीं.न.कहीं ममता की भी संलिप्तता है तभी तो वह राजीव कुमार के पक्ष में सारी मर्यादाएं और सीमा, तोड़कर खड़ी हो गई हैं। लोगों के जहन में यह भी होगा कि 15 दिसंबर 2016 को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार के कार्यालय में घोटाले के ही सिलसिले में जब छापा डालने गई तो केजरीवाल ने कैसा कोहराम मचाया था। ऐसा हंगामा खड़ा किया गया कि जैसे यह मुख्यमंत्री के कार्यालय में छापा डाला गया हो। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में ही होता है।

गनीमत है कि दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकार के अधीन है वरना केजरीवाल भी ममता सरीखे ही कुछ कर गुजरने से न चूकते। केजरीवाल द्वारा यह भी कहा गया कि उनके प्रमुख सचिव के यहां छापा डालने से पूर्व उनसे पूछा क्यों नहीं गया ठीक वैसे ही जैसे ममता ने अभी कहा कि बगैर सूचना के सीबीआई कैसे चली आईघ् यह बात अलग है कि इस संबंध में सीबीआई ने कलकत्ता पुलिस को सूचित तो किया ही था और उनसे सहयोग भी मांगा था। लोगों की याददाश्त में वर्ष 1997 की वह घटना भी होगी जब चारा घोटाले में संलिप्तता के चलते सीबीआई ने बिहार के डीजीपी से लालू यादव की गिरतारी के लिए सहयोग मांगा था, पर डीजीपी ने ऐसा कोई सहयोग देने से इंकार कर दिया था। परिणामतरू इस मामले में फौज तक से सीबीआई द्वारा सहयोग लेने की चर्चा, सामने आई थीं। उपरोक्त घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकलता हैघ् वह यही कि आजादी के बाद ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की गई। खास तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के 70 के दशक से कि अधिकारियों की निष्ठा संविधान के प्रति न होकर सत्तारूढ़ राजनेताओं के प्रति हो। फलतः पूरे देश में सत्तारूढ़ लोगों और अधिकारियों का एक गठजोड़ बन गया, जिसने देश को जमकर लूटा और जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे को पूरी ताकत से बचाने का उपक्रम करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजीव कुमार का प्रकरण है। आखिर में राजीव कुमार ने जब एसआईटी चीफके हैसियत से ममता और उनके दल को लोगों को बचाया तो ममता भी उनके बचाव में पूरी शर्मो.हया खोकर क्यों न उतरें। इसी नेता.अधिकारी गठजोड़ का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह जंगल राज कायम है। भाजपा नेताओं की सभाओं और रैलियों में व्यवधान डाला जा रहा है तो भाजपा कार्यकताओं, समथर्कों को खुले आम प्रताड़ित ही नहीं किया जा रहा, उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं।

लाख टके की बात है कि क्या किसी जांच एजेन्सी को यदि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री न चाहे तो जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके फिर कई अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी और एनआईए जैसी संस्थाओं का औचित्य ही क्या है। दूसरी बड़ी बात यह कि कोई प्रदेश क्या मुख्यमंत्रियों का जागीर है। या वह भारतीय संविधान के तहत कार्य करने को बाध्य है। तीसरी बड़ी बात यह कही जाती है कि मोदी और अमित शाह बदले की भावना से यह कर रहे हैं। बिडम्बना यह कि राबर्ट वाड्रा के विरूद्ध ईडी की जांच को लेकर भी यही कहा जा रहा है। कार्ति चिदंबर के प्रकरण में भी यही कहा गया। पर बड़ी बात यह कि सच्चे व्यक्ति को पूछताछ से क्या डरना बावजूद इसके यदि किसी को लगता है कि जांच एजेन्सिया उन्हें नाजायत ढंग से फंसा रही है तो अदालत के दरवाजे खुले ही हैं। पर अंतिम सच यही है कि मोदी के दौर में जब देश को लूटनेवालों को जवाबदेह होना पड़ रहा है तब उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि सत्ता परिवर्तन ही उनके बचने का एकमेव माध्यम है। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं चोरी और सीनाजोरी का नायाब नमूना है।

वीरेन्द्र सिंह परिहार

(ये लेखक के अपने विचार है)

राजनीतिक उठापटक में क्यों अटक गया है देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी तुलना संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर से कर दी। बस इस पर बवाल मच गया। कहा गया कि एक तरफ महाराष्ट्र में आंबेडकर भवन गिराया गया। हरियाणा और गुजरात में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे में मोदी की तुलना अम्बेडकर से कैसे हो सकती है।

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया था कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वह पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी। इस पर शिवसेना भड़क गई और उसने जवाब दिया कि कोई अगर यहां आकर पटक देने की बात करेगा, तो हम पटक.पटक के गाड़ भी देने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रामदास कदम ने केंद्र सरकार द्वारा सामान्य जाति को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय में जब मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे पेंडिंग हैं, ये नया वादा करना गलत है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि हम पिछले तीन साल से बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ही हमारे साथ रोड रोमियो की तरह चिपकी हुई है, हम तो बीजेपी की तरफ देखते भी नहीं हैं। संजय राउत ने कहा था कि तीन राज्यों के चुनाव बता रहे हैं कि किसने किसे पटका है। शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सभी 48 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के तैयार रहने को कहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस भी बयान दे चुके हैं कि वह लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटों में 40 से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

राफेल मामले में निशाने पर लिए जाने के बाद से देखा जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी को आंख दिखा रही है। शिवसेना प्रमुख ने राफेल पर जेपीसी बनाए जाने का समर्थन किया। इसके बाद भी बीजेपी ने नरम रुख अख्तियार करते हुए उद्धव ठाकरे के बयानों को नजरअंदाज किया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना नाता समाप्त कर दिया था। विशेषज्ञों ने माना था कि करीब ढाई दशक से एक साथ काम कर रही शिवसेना के भीतर इतना आत्मविश्वास भर गया था कि वह प्रदेश की आधी सीटें आसानी से जीत सकती है। हालांकि चुनाव नतीजों में साफ हो गया और शिवसेना के खेमे में 18 सीटें आई।

उत्तरप्रदेश में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष के प्रयासों को धक्का देते हुए सपा बसपा के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है, तो कांग्रेस ने भी राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि बिना कांग्रेस के सपा.बसपा के बीच महागठबंधन का सीधा.सीधा फायदा भाजपा को होगा। बब्बर ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर यह कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में होतीं तो बीजेपी को और भी ज्यादा सीटों का नुकसान होता। पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता की तृमूकां के बीच रैलियों पर रस्साकशी हो रही है तो उत्तरप्रदेश में राममन्दिर की नूरा कुश्ती और अर्द्धकुम्भ के नाम पर कुम्भ.कुम्भ हो रहा है। लगता है 2019 के चुनावों के दौरान ही नहीं, पहले और बाद में भी जबर्दस्त हिंसा हो सकती है।

अजित वर्मा

(ये लेखक के अपने विचार है)

हिंदीः भारत सीखे अबूधाबी से

संयुक्त अरब अमारात याने दुबई और अबूधाबी ने अब अपनी अदालतों में हिंदी को भी मान्यता दे दी है। अरबी और अंग्रेजी तो वहां पहले से ही चलती है। हिंदी को मान्यता मिलने का मतलब उर्दू को भी मान्यता मिलना है। हिंदी और उर्दू में फर्क कितना है घ् सिर्फ लिपि का ही तो फर्क है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अरब देश ने वहां रहनेवाले सारे भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अपने इंसाफ के दरवाजे खोल दिए हैं। अमारात की जनसंख्या 90 लाख है। उसमें 26 लाख तो भारतीय हैं और 12 लाख पाकिस्तानी हैं। इन भारतीयों और पाकिस्तानियों में कई पढ़े.लिखे और मालदार लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर मजदूर और कम पढ़े.लिखे लोग हैं। इन लोगों के लिए अरबी और अंग्रेजी के सहारे न्याय पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि अदालत में वकील क्या बहस कर रहे हैं और जजों ने जो फैसला दिया है, उसके तथ्य और तर्क क्या हैं। उन्हें जो वकील समझा देए वही ब्रह्मवाक्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बेकसूर लोगों को सजा भुगतनी होती है, जुर्माना देना पड़ता है और कभी.कभी उन्हें देश.निकाला भी दे दिया जाता है। उनकी आर्थिक मुंडाई भी जमकर होती है। ऐसे में यह जो नई व्यवस्था वहां कायम हुई है, उसका भारत और पाकिस्तान, दोनों को स्वागत करना चाहिए। स्वागत ही नहीं करना चाहिए, उससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। भारत की अदालतों में आजादी के 70 साल बाद भी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो अभी भी अपनी भेड़चाल पर अड़ा हुआ है। वहां मुकदमों की बहस अंग्रेजी में ही होती है। जहां बहस ष्अंग्रेजीष् में होती हैए वहां फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं। अभी सुना है कि उनके हिंदी अनुवाद की बात चल रही है। सच्चाई तो यह है कि देश में कानून की पढ़ाई हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरुर ली जाए लेकिन कानून की पढ़ाई के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह काम हमारे नेता कैसे करेंगे घ् वे या तो अधपढ़ हैं या अनपढ़ हैं। इन बेचारे नेताओं से आप ज्यादा उम्मीद न करें। यह काम तो देश के विद्वान वकील, जजों और कानून के प्रोफेसरों को करना होगा। जो काम भारत में सबसे पहले होना चाहिए था, वह काम संयुक्त अरब अमारात कर रहा है। अबू धाबी के शेख मंसूर अल नाह्यान को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(ये लेखक के अपने विचार है)